

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, आप सिर्फ आगे के लोगों को देख रहे हैं, हम पीछे से चिल्ला रहे हैं, आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I will come to you. ...**(Interruptions)**... All matters under Rule 266, hon. Khargeji, you can raise those matters which are not specifically provided in these rules. ...**(Interruptions)**... This matter is provided in these rules. When a matter is provided in these rules, Rule 266 does not come into picture. ...**(Interruptions)**... This is my ruling. ...**(Interruptions)**... Rule 266 comes into picture only and only when matters not specifically provided. ...**(Interruptions)**... Now, Shri Muzibulla Khan; not present. ...**(Interruptions)**... Now, Shri Sushil Kumar Modi. ...**(Interruptions)**... Shri Sushil Kumar Modi. ...**(Interruptions)**... Shri Sushil Kumar Modi. ...**(Interruptions)**...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, no, no. ...**(Interruptions)**... Chinese problem is an important problem. ...**(Interruptions)**... The aggression is there. ...**(Interruptions)**...

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Rising demand for legal recognition to marriage between people of same sex in the country

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): सभापति महोदय, मैं सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के प्रयास का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ...**(व्यवधान)**...सभापति महोदय, 33 से ज्यादा देशों ने समलैंगिक विवाह, यानी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान कर दी है। इसी सप्ताह, अमेरिका के सीनेट ने सेम सेक्स मैरिज के लिए कानून बनाया है। Japan is the only country in G7 which has not enacted same sex marriage. यहाँ तक कि एशिया के अंदर ताईवान एक ऐसा अकेला देश है, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। ...**(व्यवधान)**...भारत में भी जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, वे इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान की जाए। ...**(व्यवधान)**...सभापति महोदय, भारत के अंदर विवाह की संस्था को पवित्र माना गया है। विवाह का मतलब होता है, biological male and biological female, उसके बीच का संबंध, सदियों पुराने हमारे जो रीति-रिवाज और रिचुअल्स हैं, जो हमारी प्रथाएँ हैं, जो हमारा सांस्कृतिक लोकाचार है, ये हमारे सामाजिक मूल्यों का हिस्सा हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Mr. Raghav Chadha, the hon. Member is talking about marriage. You need to be more careful.

श्री सुशील कुमार मोदी: हिन्दू धर्म में भी विवाह को डिवाइन ओरिजिन के रूप में माना गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इसी रूप में आकृष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर सेम सेक्स मैरिज is neither recognized nor accepted in any un-codified personal laws, like the Muslim Personal Law or any codified statutory laws. Same sex marriage would cause complete havoc with the delicate balance of personal laws in the country. परिवार और बच्चों का पालन-पोषण भी इससे जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, adoption, domestic violence, divorce, wife's right to stay in marital home, इन सारी चीजों का संबंध विवाह संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि दो जज बैठकर इस प्रकार के सामाजिक मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए, समाज में इस पर डिबेट होनी चाहिए। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग, जो एक्टिविस्ट्स लोग हैं, वे भारत में पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार का कानून लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं सेम सेक्स मैरिज को वैधानिक मान्यता दिए जाने का विरोध करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूँ कि मज़बूती के साथ सेम सेक्स मैरिज के विरोध में न्यायालय में अपनी बात रखे। मैं ज्यूडिशियरी से भी आग्रह करता हूँ कि कोई ऐसा निर्णय न दें, जो इस देश के कल्चरल इथोस, यहां की संस्कृति और विचार के विपरीत हों। इस तरह का निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

SHRI BRIJLAL (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI AJAY PRATAP SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.)(Haryana): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI KAILASH SONI (Madhya Pradesh): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SULATA DEO (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

Need to extend Hill Compensatory Allowance to Postal Employees of Darjeeling and Kalimpong

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I thank you for allowing me to speak. I seek to draw the attention of this august House that the benefit of hill compensatory allowance has been given to North-Eastern and Sikkim postal employees. But the same has not been given to the postal employees of the hilly region of Darjeeling and Kalimpong. If Sikkim can get, can fall under North-East India, why is Darjeeling and Kalimpong region not included?

Therefore, Sir, I would urge upon the hon. Finance Minister to include the postal employees of Kalimpong and Darjeeling hills for granting hill compensatory allowance to them as well. Thank you.